



2026:AHC:32580

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

WRIT - A No. - 1077 of 2026

Yogesh Yadav

.....Petitioner(s)

Versus

State Of U.P. And 2 Others

.....Respondent(s)

Counsel for Petitioner(s)	: Samarth Singh, Sanjeev Kumar Yadav
Counsel for Respondent(s)	: C.S.C.

Court No. - 33

HON'BLE VIKAS BUDHWAR, J.

1. Heard Sri Samarth Singh, learned counsel for the writ petitioner and Sri P.K. Srivastava, learned Chief Standing Counsel for the State.

2. This Court entertained the writ petition on 29.01.2026 and sought instructions. The instructions have been produced and are taken on record as Appendix–A, as noticed in the order dated 10.02.2026.

3. Sri Pramod Kumar Srivastava, learned Additional Chief Standing Counsel submits that he is well equipped with the instructions and the instructions are self sufficient for disposal of the writ petition and he does not propose to file any further affidavits and the petition be decided on the basis of the documents available on record, thus with the consent of parties, the writ petition is being decided at the fresh stage.

4. The case of the writ petitioner is that he is a Class-III employee of Madhyamik Shiksha Parishad Inter College Meerut however by virtue of the order dated 13.01.2026 passed by the Secretary Madhyamik Shiksha Parishad, U.P. Prayagraj, the petitioner has been transferred from the Madhyamim Shiksha Parishad, Regional Office, Meerut to Madhyamik Shiksh Parishad, Regional Office, Bareilly. Consequentially, on 14.01.2026, a relieving order was came to be passed by the respondent no. 3/ Under Secretary, Madhyamik Shiksha Parishad Regional Office, Meerut.

5. Questioning the orders dated 13.1.2026 and 14.1.2026, the present writ

petition has been filed.

6. Learned counsel for the petitioner submits that the impugned transfer order is stigmatic in nature. It is further submitted that the order recites that the petitioner was found responsible for misplacing eleven files and that on the basis of a preliminary inquiry report dated 18.09.2025, he was prima facie found involved in committing misconduct. It further directs that he be not posted on a sensitive seat. Reliance has been placed upon the judgment of the Hon'ble Supreme Court passed in ***Somesh Tiwari v. Union of India 2009 (2) SCC 592.***

7. Per contra, learned Additional Chief Standing Counsel submits that the petitioner has been transferred on administrative basis though in the order dated 13.1.2026 there happens to be recital about certain allegations levelled against the writ petitioner involving in misplacing of eleven files and direction for conducting inquiry in that regard. However, he fairly submits that liberty may be granted to the competent authority to pass a fresh order in accordance with law.

8. I have heard learned counsel for the parties and perused the record carefully.

9. The relevant extract of the impugned order dated 13.01.2026 impugned in the writ petition reads as under:-

"श्री योगेश यादव, वरिष्ठ सहायक, माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ द्वारा इण्टर २४ प्रमाण पत्र अनुभाग की कार्यवाही में रसीद अनुभाग से नाम संशोधन से संबंधित 11 पत्रावलियाँ दिनांक:- 20.09.2024 को प्राप्त की गयी। उक्त नाम संशोधन से संबंधित 11 पत्रावलियाँ श्री गुरवचन सिंह, मोहल्ला- थापरनगर, निकट- गुरुद्वारा, गली नं0-2 जनपद-मेरठ के दिनांक रहित पत्र सम्प्रति दिनांक 24.07.2025 को परिषद कार्यालय में यह उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया गया कि उक्त पत्रावलियों उसे थापरनगर, मेरठ की गली में प्राप्त हुई है।

प्रश्नगत प्रकरण में अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ को अविहित पत्रांक: मा०शि०प०/नियोजन/533 दिनांक:- 31-07-2025 द्वारा संदर्भगत प्रकरणों में आवश्यक कार्यवाही 'सहित सम्बन्धित कर्मचारी से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के साथ ही उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए प्रकरण की तथ्यात्मक आख्या मुख्यालय, प्रयागराज को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी। तदोपरान्त अपर सचिव, मा०शि०प०,

क्षेत्र, मेरठ के अविहित पत्रांक: क्षेत्र/मांशिप/मे/प्रबन्ध/320 दिनांक: 22-09-2025 के साथ जाँच अधिकारी श्री रवीन्द्र पाल सिंह, उप सचिव (प्रशासन), मांशिप, क्षेत्र मेरठ की जांच आख्या दिनांक 18.09.2025 द्वारा उपलब्ध करायी गयी। उक्त जाँच अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रारम्भिक जाँच आख्या में आपको प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाया है।

आप द्वारा इण्टर प्रमाण पत्र अनुभाग की कार्यावधि में दिनांक 20.09.2024 को प्राप्त हुए नाम संशोधन से संबंधित 11 पत्रावलियों पर प्रशासनिक अधिकारी के संशोधन हेतु अभिमत दिये जाने के उपरान्त लगभग 01 वर्ष तक अपने पास रखा जाना तथा लगभग एक वर्ष बीत जाने के बाद भी उक्त पत्रावलियों के सम्बन्ध में कोई संज्ञान नहीं लिया जाना एवं पत्रावलियों के गुम हो जाने सम्बन्धी जानकारी अधिकारियों को नहीं दिया जाना घोर आपत्तिजनक, स्वेच्छाचारिता का द्योतक होने के साथ-साथ परिषदीय कार्य प्रणाली के विपरीत है। आपका यह कृत्य उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के प्रतिकूल है आपके इस कृत्य से आम जनमानस में परिषद् कार्यालय की छवि धूमिल हुई है जिसके लिये आप दोषी हैं।

उपर्युक्तानुसार श्री योगेश यादव, वरिष्ठ सहायक, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ द्वारा किये गये कृत्यों एवं शासकीय कार्यों के प्रति वरती गई घोर लापरवाही / उदासीनता के दृष्टिगत निम्नवत आदेश प्रदान किये जाते हैं:-

1. श्री योगेश यादव, वरिष्ठ सहायक द्वारा किये गये कृत्यों एवं शासकीय कार्यों के प्रति वरती गई घोर लापरवाही / उदासीनता के दृष्टिगत प्रकरण में जाँच अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रारम्भिक जाँच आख्या के आलोक में उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के उपबन्धों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की विभागीय जाँच हेतु श्री स्कन्द शुक्ल, अपर सचिव (शोध), माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को पदेन जाँच अधिकारी नामित किया जाता है।

2. श्री योगेश यादव, वरिष्ठ सहायक, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ को उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग-4 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या:-1/ 2025/119/सामान्य / सैंतालीस-का-4-2025-1/3/96 दिनांक 06.05.2025 में निहित प्राविधानों के आलोक में शासन के पत्र संख्या:-2047 / पन्द्रह-2-2026 दिनांक 09.01.2026 द्वारा प्राप्त शासकीय अनुमति के अनुक्रम में प्रशासनिक आधार पर माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली में स्थानान्तरण करते हुये आदेश निर्गमन की तिथि से स्वतः कार्यमुक्त किया जाता है तथा उन्हें निर्देशित किया जाता है कि आदेश प्राप्ति की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर स्थानान्तरित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

3.. श्री योगेश यादव, वरिष्ठ सहायक को माध्यमिक शिक्षा परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली

के किसी भी महत्वपूर्ण / संवेदनशील अनुभाग में कार्य करने हेतु कदापि पदस्थित न किया जाय।"

10. The order impugned dated 13.1.2026 reveals that petitioner was prima facie found involved in misplacement of eleven files and that a preliminary inquiry report held him blameworthy.

11. The inclusion of such findings and imputations in the transfer order clearly casts a stigma upon the petitioner. Admittedly, no regular departmental inquiry culminating in a final finding of guilt has been conducted. In view of the law laid down in Somesh Tiwari (supra), an order of transfer containing stigmatic remarks founded on alleged misconduct cannot be sustained.

12. Accordingly, the writ petition is allowed in part.

13. The order dated 13.01.2026 passed by the Secretary Madhyamik Shiksha Parishad, U.P. Prayagraj transferring the petitioner from Meerut to Bareilly, as well as the consequential relieving order dated 14.01.2026 passed by the Under Secretary, Madhyamik Shiksha Parishad, Regional Office, Meerut, are hereby set aside.

14. It is, however, made clear that setting aside of the aforesaid orders shall not preclude the respondents from passing a fresh order of transfer, if so required, strictly on administrative grounds and in accordance with law, or from initiating appropriate disciplinary proceedings in accordance with law.

(Vikas Budhwar,J.)

February 12, 2026
Sushma